प्रेस विज्ञप्ति

02/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने मेसर्स येकनेल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और कई संबद्ध संस्थाओं से जुड़े व्यापार-आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) सिंडिकेट के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) 28/11/2025 को दर्ज की है। शिकायत में बताया गया है कि कैसे आयात करने वाली शेल कंपनियों ने धोखाधड़ी से अधिक मूल्य वाले आयात भुगतान को विदेश में भेजा, जिससे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 और 135 के तहत निर्धारित अपराधों से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) का शोधन किया गया।

जांच में एक परिष्कृत व्यापार-आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) योजना का पता चला है जिसमें एक सिंडिकेट ने भारत के बाहर धन को धोखाधड़ी से भेजने के लिए आयात करने वाली शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क का निर्माण और नियंत्रण किया। इन डमी कंपनियों ने सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं और सीमा शुल्क गृह एजेंटों (सीएचए) के साथ मिलीभगत करके तैयार किए गए अधिक-इनवॉइस किए गए आयात दस्तावेजों और मनगढ़ंत मूल्यांकन रिपोर्टों का उपयोग करके कम मूल्य वाले पत्थरों के आयात को उच्च मूल्य वाले कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के रूप में घोषित किया। भारत के भीतर कई शेल संस्थाओं के माध्यम से पहले धन को स्तरित किया गया और फिर कथित आयात भुगतान के रूप में विदेश में भेजा गया, जिससे सिंडिकेट को वैध व्यापार के बहाने सैकड़ों करोड़ रुपये अवैध रूप से देश से बाहर स्थानांतरित करने में मदद मिली।

इस मामले में, लगभग 3.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति, जिसमें एक आवासीय फ्लैट भी शामिल है, को कुर्क करने के लिए अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए गए हैं। इन संपत्तियों को टीबीएमएल संचालन से प्राप्त पीओसी या समकक्ष मूल्य के रूप में पहचाना गया है, जिसे कई शेल संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।

धन शोधन के अपराध में अन्य संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी और भारत और विदेशों में पीओसी का पता लगाने के संबंध में आगे की जांच जारी है।